>

Title: Need to waive off all the loans and release funds to drought affected farmers of Madhya Pradesh.

श्री गणेश सिंह : सभापति महोदय, मैं सूखे एवं अकाल के संबंध में भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। देश के कई राज्यों में कम वर्षा के कारण अकाल एवं पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है। प्रदेश में 48 जिलों में से 39 जिलों की 164 तहसीलें भयंकर सूखे की चपेट में हैं।[h63] किसान पूरी तरह से निराश हो चुका है तथा कर्ज के बोझ से लद चुका है, इसलिए मजबूरन आत्महत्या करने पर उतारू हो रहा है। पूरे क्षेत्र में भुखमरी तथा पलायन की स्थिति निर्मित हो गई है। केन्द्र सरकार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को खाद्यान्न देती थी, उसमें भी कटौती कर ली गई है। पेयजल के सभी स्त्रोत पूरे जिले में सूख गए हैं। मैंने सतना के लोगों को पीने का पानी देने के लिए 110 किलोमीटर लम्बी दूरी तय करके, माननीय मुख्य मंत्री जी के संकल्प के मुताबिक बाण सागर से पानी ला करके लोगों को दे रहे हैं।

महोदय, प्रदेश सरकार ने 24242 करोड़ का पैकेज सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने हेतु मांग की है। इसी बीच केन्द्रीय अध्ययन दल ने भी वहां की भयावह स्थिति को देखा है, किन्तु दुर्भाग्य है कि आज तक केन्द्र सरकार ने फूटी कौड़ी तक नहीं दी। वर्ष 2007-08 के लिए केन्द्र ने जो सीआरएफ में 269.29 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया था, वह जनवरी माह में ही खत्म हो चुका है।

महोदय, मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि प्रभावित क्षेत्र के किसानों के पूरे कर्जे माफ किए जाएं। साथ ही सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार की मांग के अनुसार 24244 करोड़ की तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए। धन्यवाद।